

अनुभव

जिम्मेदारी

हजारों सफलताओं की एक पहचान

ध्येय IAS...

अब नये प्रारूप में

IAS/PCS परीक्षाओं की मांग के अनुरूप

महत्वपूर्ण लेख विश्लेषण

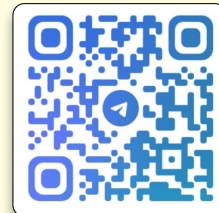
Date:- 22-03-2026

INDEX

Sr. No.	Editorial	Source	Page No.
1	Natanz attack: How nuclear sites could pose radiation risks if damaged	The Hindu	02-12
2.	As war in West Asia drags on, why government and RBI need a plan for the economy	The Indian Express	13-22
3.	Millions of citizen non-voters!	The Indian Express	23-32
4.	Why the war in Iran gives India a chance to put its own house in order	The Indian Express	33-42
5.	India is opposing a China-led WTO investment deal, even at the risk of isolation. Here's why	The Indian Express	43-52
6.	Are we measuring global warming wrong: What a new study says	The Indian Express	53-64

TO GET FREE ACADEMIC SUPPORT

SCAN THIS QR CODE & JOIN



(Scan with Google Lens)

PRAYAGRAJ: II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil, Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068

ALIGANJ: A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow (UP). Ph : 0522-4045320, 7619903300

GOMTI NAGAR: CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5 Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar Lucknow-226010 (UP). Ph: 7234000501, 7570009003

1 Natanz attack: How nuclear sites could pose radiation risks if damaged

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेख का तर्क है कि परमाणु स्थलों पर सैन्य हमले केवल रणनीतिक जोखिम ही नहीं बल्कि गंभीर रेडियोलॉजिकल और पर्यावरणीय खतरे भी पैदा कर सकते हैं।

❖ **Author:** Anagha Jayakumar, Amitabh Sinha

UPSC GS Reference

GS Paper: GS-2 (International Relations) + GS-3 (Science & Technology / Internal Security / Environment)

Syllabus Keywords:

Nuclear Proliferation, Nuclear Safety, Radiation Risk, Radiation Risk, West Asia Conflict, IAEA Monitoring

1-Line Relevance

Iran's Natanz nuclear plant attack highlights nuclear security, radiation risk, and global nuclear governance challenges

Article Summary

भूमिका

हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईरान के Natanz (नतांज) यूरेनियम संवर्धन संयंत्र पर अमेरिका और इज़राइल द्वारा हमला एक गंभीर सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंता बनकर उभरा है। Natanz ईरान के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र रहा है जहाँ बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज मशीनों द्वारा यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार इस हमले में कुछ संरचनात्मक क्षति हुई, हालांकि तत्काल रेडिएशन रिसाव की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु स्थलों पर

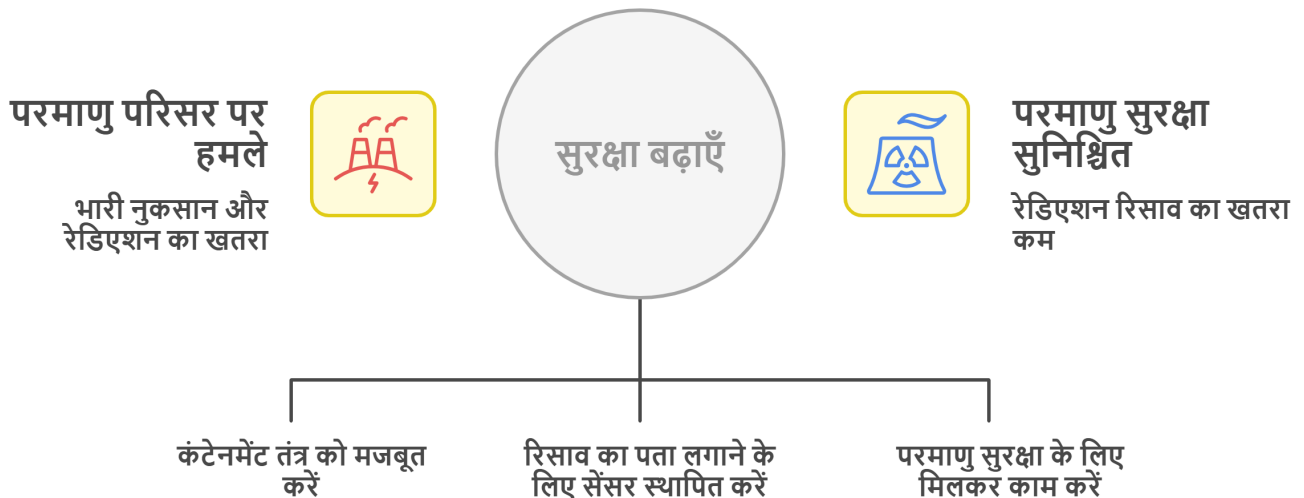
हमले रेडियोलॉजिकल प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और वैश्विक सुरक्षा अस्थिरता को जन्म दे सकते हैं। यह घटना परमाणु सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र की सीमाओं को भी उजागर करती है।

मुख्य भाग

पहला महत्वपूर्ण पहलू Natanz परमाणु परिसर की संरचना और रणनीतिक महत्व से जुड़ा है। यह परिसर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य संवर्धन केंद्र है जिसमें दो प्रमुख संयंत्र शामिल हैं—Fuel Enrichment Plant (FEP) और Pilot Fuel Enrichment Plant (PFEP)। FEP एक विशाल भूमिगत सुविधा है जिसे लगभग 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जून 2025 के हमलों से पहले यहाँ लगभग 17,000 सेंट्रीफ्यूज स्थापित थे, जिनमें से 13,500 सक्रिय थे और 5% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहे थे। दूसरी ओर PFEP एक शोध-आधारित सुविधा थी जहाँ उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक संवर्धन किया जाता था। उपग्रह चित्रों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार पिछले हमलों में इन सुविधाओं को भारी नुकसान पहुँचा और कई सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परमाणु स्थलों पर हमले केवल सैन्य क्षति तक सीमित नहीं रहते बल्कि रेडिएशन और रासायनिक रिसाव का खतरा पैदा करते हैं। परमाणु संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थ विभिन्न रूपों में संग्रहीत होते हैं, जैसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस (UF₆) या रेडियोधर्मी धूल। ये पदार्थ अस्थिर होते हैं और समय के साथ विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि किसी सैन्य हमले के कारण सुरक्षा प्रणालियाँ या कंटेनमेंट तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाएँ, तो रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण, जल स्रोतों या खाद्य श्रृंखला में फैल सकते हैं। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कैंसर, डीएनए क्षति और पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

Natanz परमाणु परिसर पर हमलों का प्रभाव

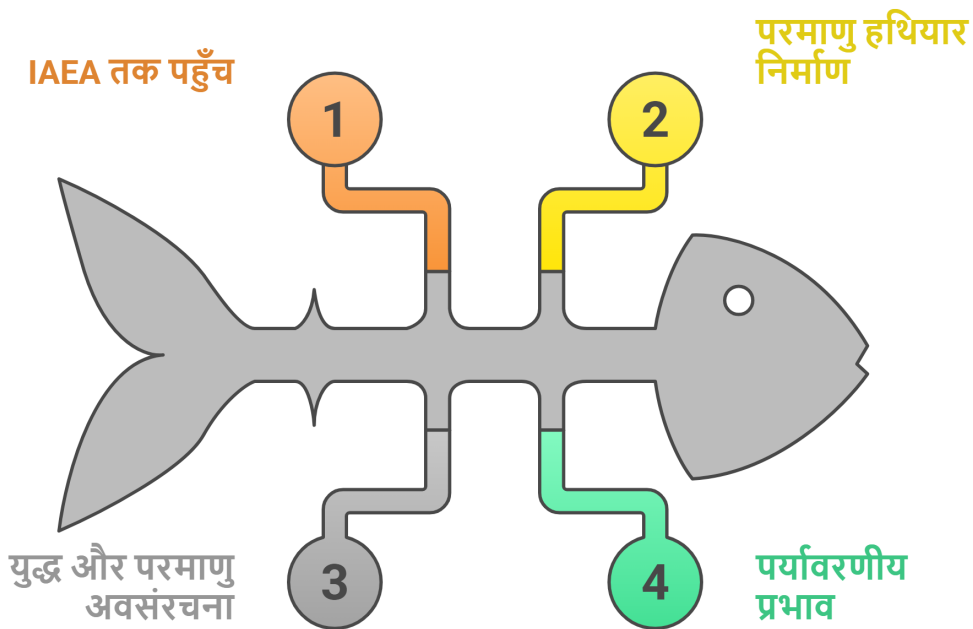


तीसरा पहलू वैश्विक परमाणु निगरानी और सुरक्षा शासन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का उद्देश्य विश्व में परमाणु गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन हालिया घटनाओं में एजेंसी को ईरान की परमाणु सुविधाओं तक आठ महीने से अधिक समय से पहुँच नहीं मिल सकी है। इस कारण ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम के भंडार की वर्तमान स्थिति अस्पष्ट है। यह स्थिति वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है क्योंकि उच्च-स्तरीय संवर्धित यूरेनियम (90% या उससे अधिक) परमाणु हथियार निर्माण में उपयोग किया जा सकता है।

चौथा महत्वपूर्ण पहलू युद्ध और परमाणु अवसंरचना के बीच खतरनाक संबंध को दर्शाता है। इतिहास में 1986 का Chernobyl हादसा और 2011 का Fukushima दुर्घटना यह दिखाते हैं कि परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाएँ कितनी व्यापक पर्यावरणीय और मानव क्षति का कारण बन सकती हैं। हाल के वर्षों में यूक्रेन के Zaporizhzhia

परमाणु संयंत्र पर युद्ध के दौरान हुए हमले भी इसी खतरे को रेखांकित करते हैं। यदि Natanz जैसे संयंत्रों में व्यापक क्षति होती है तो इसका प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकता है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित वैश्विक चिंताएँ



निष्कर्ष

Natanz पर हमला यह दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध में परमाणु अवसंरचना कितनी संवेदनशील और जोखिमपूर्ण है। यद्यपि तत्काल रेडिएशन रिसाव की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी ऐसे हमले परमाणु सुरक्षा मानकों और वैश्विक अप्रसार व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं। परमाणु स्थलों पर सैन्य कार्रवाई से पर्यावरणीय आपदा, स्वास्थ्य संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक

है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय IAEA की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करे, संघर्ष क्षेत्रों में परमाणु सुविधाओं को संरक्षित करने के लिए वैश्विक नियम बनाए और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे। दीर्घकालिक दृष्टि से परमाणु सुरक्षा केवल तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक शांति और मानव सुरक्षा का प्रश्न है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : Natanz परमाणु संयंत्र पर सैन्य हमला ● Core claim : परमाणु स्थलों पर हमले गंभीर रेडिएशन और सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं ● Reason-1 : रेडियोधर्मी पदार्थों का संभावित रिसाव ● Reason-2 : परमाणु निगरानी और अप्रसार व्यवस्था कमजोर होना ● Trade-off : सैन्य रणनीति बनाम वैश्विक पर्यावरणीय सुरक्षा ● Way forward : कूटनीति, IAEA निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IAEA ने Natanz साइट पर संरचनात्मक क्षति और स्थानीय प्रदूषण की संभावना की पुष्टि की, परंतु बाहरी रेडिएशन वृद्धि नहीं पाई। 2. जून 2025 के हमलों में Natanz के Fuel Enrichment Plant की बिजली संरचना नष्ट हो गई जिससे हजारों सेंटीप्यूज क्षतिग्रस्त हुए। 3. ईरान के 60% संवर्धित यूरेनियम के भंडार का स्थान वर्तमान में अज्ञात है क्योंकि IAEA को आठ महीनों से निरीक्षण की अनुमति नहीं मिली।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि परमाणु स्थलों पर हमले ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए आवश्यक रणनीतिक कदम हो सकते हैं। उनका मानना है कि ऐसे हमले संभावित परमाणु प्रसार को रोक सकते हैं। हालांकि यह तर्क सीमित है क्योंकि परमाणु संयंत्रों पर हमला क्षेत्रीय पर्यावरणीय आपदा और वैश्विक सुरक्षा संकट को जन्म दे सकता है। इसलिए सैन्य विकल्प के बजाय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय निगरानी अधिक सुरक्षित और टिकाऊ समाधान हैं।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) IAEA Safeguards Mechanism 	<ol style="list-style-type: none"> Uranium Enrichment <ul style="list-style-type: none"> Definition: वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। Example: 3-5% संवर्धन परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त होता है। Centrifuge <ul style="list-style-type: none"> Definition: तेज गति से घूमने वाली मशीन जो यूरेनियम समस्थानिकों को अलग करती है। Example: Natanz संयंत्र में हजारों सेंट्रीफ्यूज स्थापित थे।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Uranium enrichment levels (3–5% vs 90%) ● Radiological contamination risk ● Nuclear safety during armed conflict ● Strategic importance of underground nuclear facilities 	<p>3. Highly Enriched Uranium (HEU)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: 90% या उससे अधिक U-235 वाला यूरेनियम, जो परमाणु हथियारों के लिए उपयोगी होता है। ● Example: परमाणु बम निर्माण में HEU का उपयोग किया जाता है। <p>4. Radiological Contamination</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों का फैलाव जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा होता है। ● Example: Chernobyl दुर्घटना के बाद बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैल गया था। <p>5. Uranium Hexafluoride (UF6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया में प्रयुक्त गैसीय यौगिक। ● Example: संवर्धन संयंत्रों में UF6 को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:-1

परमाणु स्थलों पर सैन्य हमलों से उत्पन्न रेडिएशन और पर्यावरणीय जोखिमों की चर्चा कीजिए।

Keywords: Nuclear facility, Radiation risk, Uranium enrichment, Nuclear safety, Environmental impact, IAEA, Armed conflict, Radioactive contamination

Model Answer Draft

Introduction:

परमाणु संयंत्र आधुनिक ऊर्जा और रणनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, किंतु इन पर सैन्य हमले गंभीर रेडिएशन और पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकते हैं। हाल ही में ईरान के Natanz परमाणु संयंत्र पर हमले ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध और परमाणु अवसंरचना का संयोजन वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है।

Body:

सबसे पहला जोखिम रेडियोधर्मी पदार्थों के रिसाव का है। परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम विभिन्न रूपों में संग्रहित होता है, जैसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस या रेडियोधर्मी धूल। यदि हमले के कारण कंटेनमेंट सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाएँ, तो ये पदार्थ वातावरण, जल और खाद्य श्रृंखला में फैल सकते हैं।

दूसरा जोखिम मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव का है। रेडिएशन से डीएनए क्षति, कैंसर, जन्म दोष और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इतिहास में Chernobyl (1986) और Fukushima (2011) जैसी घटनाएँ इस खतरे के गंभीर परिणामों को दर्शाती हैं।

तीसरा पहलू वैश्विक परमाणु सुरक्षा और अप्रसार व्यवस्था पर प्रभाव का है। युद्ध के दौरान IAEA जैसे संस्थानों की निगरानी कमजोर हो सकती है, जिससे संवर्धित यूरेनियम के भंडार और परमाणु गतिविधियों की पारदर्शिता कम हो जाती है।

Conclusion:

इसलिए परमाणु स्थलों पर सैन्य हमले केवल रणनीतिक निर्णय नहीं बल्कि मानव सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा हैं। वैश्विक समुदाय को कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय निगरानी और परमाणु सुरक्षा मानकों को मजबूत कर ऐसे जोखिमों को कम करना चाहिए।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Nuclear safety + environmental link ● Global governance (IAEA) mention ● Historical disasters examples 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nuclear weapons vs nuclear power confusion ● केवल सैन्य दृष्टिकोण पर उत्तर सीमित करना

प्रश्न:-2

वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: NPT, IAEA, Nuclear proliferation, Monitoring gaps, Strategic conflict, Uranium enrichment, International governance

Model Answer Draft

Introduction:

परमाणु अप्रसार व्यवस्था का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख स्तंभ Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) और IAEA निगरानी तंत्र हैं, फिर भी हाल की घटनाएँ इसकी सीमाओं को उजागर करती हैं।

Body:

पहली सीमा राजनीतिक और रणनीतिक हितों का टकराव है। कई देश सुरक्षा चिंताओं के कारण परमाणु क्षमता विकसित करना चाहते हैं, जिससे अप्रसार समझौतों का पालन कठिन हो जाता है।

दूसरी सीमा निगरानी और पारदर्शिता की कमी है। यदि किसी देश द्वारा निरीक्षण की अनुमति सीमित कर दी जाए, तो IAEA को परमाणु गतिविधियों का सही आकलन करने में कठिनाई होती है। ईरान के मामले में लंबे समय तक निरीक्षण न हो पाना इसका उदाहरण है।

तीसरी सीमा सैन्य संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव है। युद्ध की स्थिति में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और निगरानी दोनों प्रभावित होती हैं, जिससे परमाणु जोखिम बढ़ जाता है।

Conclusion:

इस प्रकार वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था अभी भी कई चुनौतियों से घिरी है। इसे प्रभावी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता, और मजबूत निरीक्षण तंत्र आवश्यक हैं, ताकि परमाणु ऊर्जा का उपयोग मानव कल्याण के लिए सुरक्षित रूप से किया जा सके।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • NPT + IAEA linkage • Real-world example (Iran case) • Governance reform suggestion 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल सिद्धांत लिखना, उदाहरण न देना • निष्कर्ष में समाधान न देना

Case Study

1. **Chernobyl Disaster (1986)** - सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना
2. **Fukushima Nuclear Accident (2011)** - प्राकृतिक आपदा से परमाणु रिसाव
3. **Zaporizhzhia Nuclear Plant (Ukraine War)** - युद्ध क्षेत्र में परमाणु संयंत्र का जोखिम

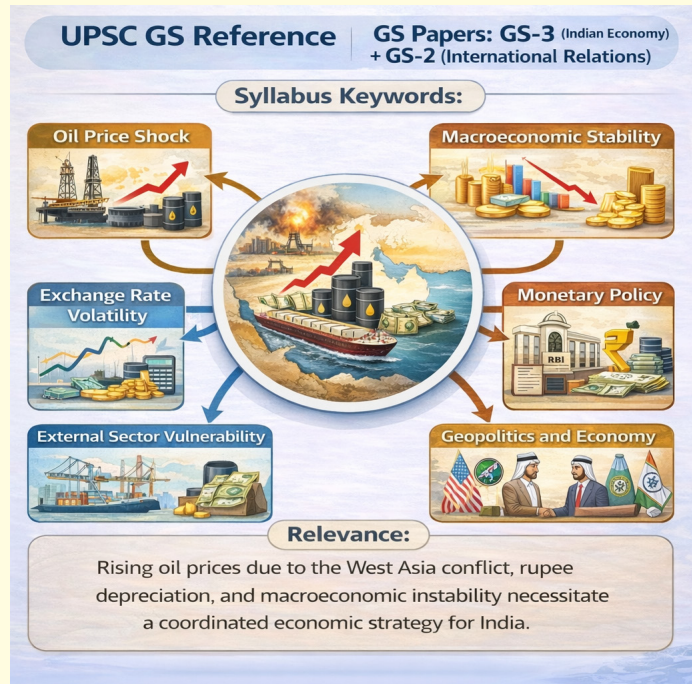
2

As war in West Asia drags on, why government and RBI need a plan for the economy

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेखकों का मत है कि पश्चिम एशिया युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए भारत सरकार और RBI को समन्वित व पूर्व-तैयार आर्थिक रणनीति बनानी चाहिए।

❖ **Author:** Siddharth Upasani, Aanchal Magazine



Article Summary

भूमिका

पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध केवल भू-राजनीतिक संकट नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। भारत जैसे ऊर्जा-आयात पर निर्भर देश के लिए इसका प्रभाव और अधिक गहरा हो सकता है। हाल के सप्ताहों में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक अनिश्चितता और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव के कारण रुपये में गिरावट देखी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये का स्तर 93 के पार पहुँचना इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष भारतीय

अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए एक समन्वित आर्थिक रणनीति तैयार करना आवश्यक हो जाता है ताकि संभावित झटकों से अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखी जा सके।

मुख्य भाग

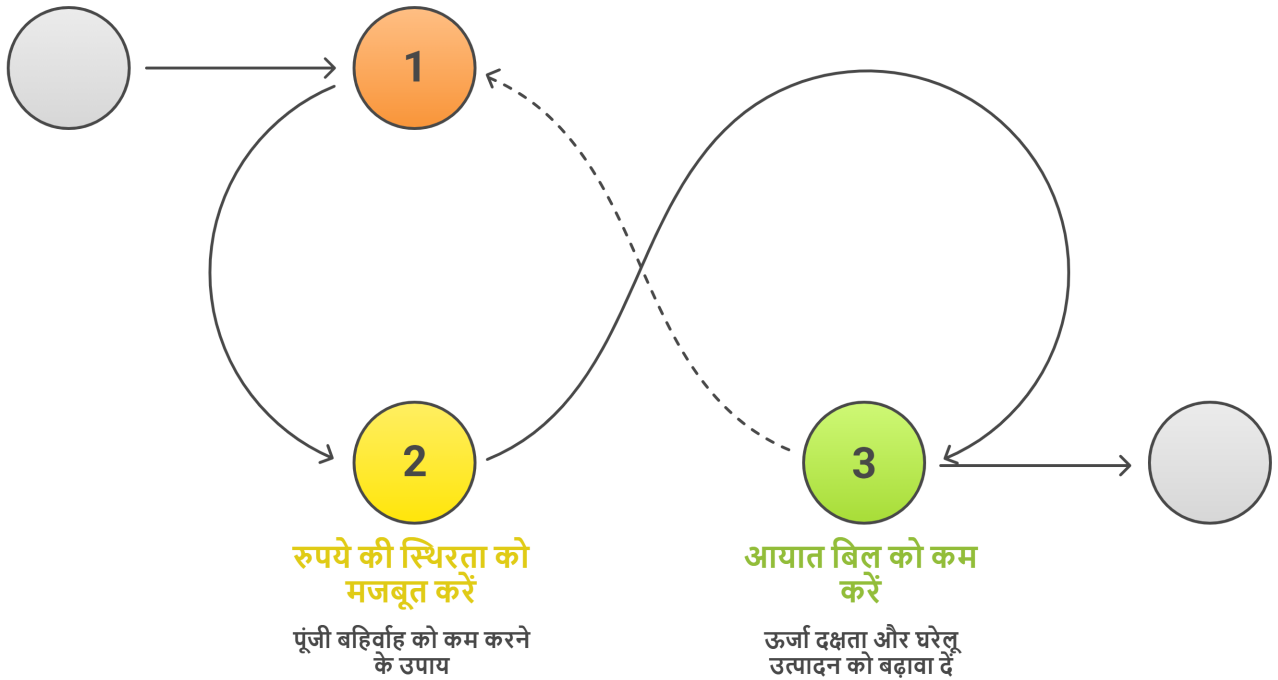
पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात बिल पर सीधा प्रभाव डालता है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें पश्चिम एशिया का बड़ा योगदान है। यदि युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे भारत का आयात बिल बढ़ेगा और चालू खाते का घाटा (Current Account Deficit) बढ़ सकता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक तेल कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई हैं और भारत के तेल बास्केट की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है। यह स्थिति भारत की महँगाई और वित्तीय स्थिरता पर दबाव डाल सकती है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता है। वैश्विक संकट के समय निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जाते हैं, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का बहिर्वाह होता है। परिणामस्वरूप रुपये पर दबाव बढ़ता है। हाल ही में रुपये का स्तर 93 प्रति डॉलर के पार चला जाना इस बात का संकेत है कि बाजार युद्ध की अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं। रुपये की कमजोरी से आयात महँगा हो जाता है, जिससे महँगाई और बढ़ सकती है।

पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत पर प्रभाव

ऊर्जा स्रोतों में विविधता

तेल आयात पर निर्भरता कम करें

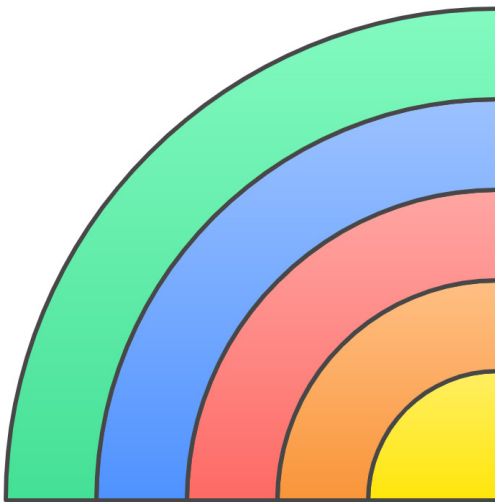


तीसरा पहलू मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन का है। तेल कीमतों में वृद्धि से परिवहन, उत्पादन और ऊर्जा लागत बढ़ती है, जिससे व्यापक महँगाई पैदा होती है। ऐसी स्थिति में RBI को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति कड़ी करनी पड़ सकती है। लेकिन ब्याज दरों में वृद्धि से निवेश और आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नीति निर्माताओं के लिए यह संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

चौथा पहलू नीतिगत समन्वय और पूर्व-तैयारी का है। लेख के अनुसार भारत को केवल अल्पकालिक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक व्यापक आर्थिक योजना तैयार करनी चाहिए। इसमें तेल आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की खोज, रणनीतिक

पेट्रोलियम भंडार का उपयोग, वित्तीय बाजारों की स्थिरता बनाए रखना और विदेशी मुद्रा भंडार का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार और RBI के बीच समन्वय आवश्यक है ताकि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ मिलकर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकें।

मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन



पूर्व-तैयारी

तेल आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों और रणनीतिक भंडार

नीतिगत समन्वय

आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और RBI समन्वय

आर्थिक वृद्धि

ब्याज दरों में वृद्धि से निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव

मौद्रिक नीति

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि

मुद्रास्फीति

तेल की कीमतों में वृद्धि से व्यापक महँगाई

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी चुनौती बन सकता है, जिसमें तेल कीमतों का झटका, विनिमय दर की अस्थिरता और मुद्रास्फीति का दबाव शामिल है। ऐसे समय में नीति निर्माताओं के लिए केवल संकट के बाद प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय भारत को पूर्व-तैयारी, नीति समन्वय और दीर्घकालिक ऊर्जा एवं आर्थिक रणनीति अपनानी होगी। यदि सरकार और RBI मिलकर समय रहते स्पष्ट आर्थिक योजना तैयार करते हैं, तो भारत न केवल इस संकट से उबर सकता है बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी आर्थिक स्थिरता भी बनाए रख सकता है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : पश्चिम एशिया युद्ध से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता ● Core claim : भारत को आर्थिक झटकों से बचने के लिए पूर्व-तैयार नीति चाहिए ● Reason-1 : तेल आयात बिल और चालू खाते पर दबाव ● Reason-2 : रुपये की गिरावट और पूंजी बहिर्वाह ● Trade-off : महँगाई नियंत्रण बनाम आर्थिक वृद्धि ● Way forward : सरकार-RBI समन्वय और ऊर्जा रणनीति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये का विनिमय दर 93 प्रति डॉलर के पार पहुँचा, जो युद्ध के प्रभाव का संकेत है। 2. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँचीं। 3. भारत के तेल बास्केट की कीमत लगभग 156 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और विविधीकृत व्यापार के कारण ऐसे बाहरी झटकों को आसानी से झेल सकती है। हालांकि यह तर्क पूरी तरह पर्याप्त नहीं है क्योंकि लंबा चलने वाला युद्ध ऊर्जा कीमतों और वित्तीय बाजारों में लगातार अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए केवल आर्थिक मजबूती पर निर्भर रहने के बजाय पूर्व-नियोजित नीतिगत रणनीति आवश्यक है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Strategic Petroleum Reserves (SPR) 	<p>1. Current Account Deficit (CAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: किसी देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर। Example: तेल आयात बढ़ने से भारत का CAD बढ़ सकता है।
<ul style="list-style-type: none"> Current Account Deficit (CAD) 	<p>2. Exchange Rate</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के मुकाबले कीमत। Example: रुपये का 93 प्रति डॉलर होना विनिमय दर का उदाहरण है।
<ul style="list-style-type: none"> Exchange Rate Volatility 	<p>3. Imported Inflation</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने से घरेलू महँगाई बढ़ना। Example: तेल कीमत बढ़ने से भारत में पेट्रोल महँगा होना।
<ul style="list-style-type: none"> Imported Inflation 	<p>4. Strategic Petroleum Reserve</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: आपात स्थिति के लिए सरकार द्वारा संग्रहित तेल भंडार। Example: भारत के विशाखापट्टनम और मंगलौर में SPR भंडार।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> • Monetary–Fiscal Policy Coordination • Energy Security Strategy 	<p>5. Monetary Policy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definition: केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर और धन आपूर्ति को नियंत्रित करने की नीति। • Example: RBI महँगाई नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ा सकता है।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: Geopolitics, Oil prices, Exchange rate, Inflation, External sector, Energy security, Global shocks, Monetary policy

Model Answer Draft

Introduction:

वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक घटनाओं से गहराई से प्रभावित होती हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशिया जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में युद्ध या संघर्ष ऊर्जा बाजार, व्यापार प्रवाह और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं। भारत, जो ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर है, ऐसे भू-राजनीतिक संकटों से विशेष रूप से प्रभावित होता है।

Body:

सबसे पहला प्रभाव तेल कीमतों में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है और चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है।

दूसरा प्रभाव रुपये की विनिमय दर में गिरावट के रूप में सामने आता है। वैश्विक अनिश्चितता के समय विदेशी निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का बहिर्वाह होता है। इससे रुपये पर दबाव बढ़ता है और आयातित वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं।

तीसरा प्रभाव मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे व्यापक महँगाई पैदा होती है। इससे केंद्रीय बैंक को सख्त मौद्रिक नीति अपनानी पड़ सकती है।

Conclusion:

इस प्रकार भू-राजनीतिक संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करते हैं। इसलिए भारत को ऊर्जा विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण और मजबूत आर्थिक नीतियों के माध्यम से इन बाहरी झटकों से अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाना चाहिए।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Energy security link ● External sector explanation ● Policy solutions 	<ul style="list-style-type: none"> ● केवल तेल कीमतों तक उत्तर सीमित करना ● आर्थिक अवधारणाओं का उल्लेख न करना

प्रश्न:-2

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: Energy imports, Strategic reserves, Oil shocks, Inflation, Economic stability, Energy diversification, Renewable energy

Model Answer Draft

Introduction:

ऊर्जा किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास की आधारशिला है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है।

Body:

पहला पहलू यह है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस से पूरा होता है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

दूसरा पहलू यह है कि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति और उत्पादन लागत को बढ़ा देती है। इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है और आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है।

तीसरा पहलू ऊर्जा सुरक्षा रणनीतियों का है। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार जैसे कदम उठाए हैं। ये उपाय बाहरी झटकों के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

Conclusion:

अतः ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच गहरा संबंध है। दीर्घकालिक रूप से भारत को ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और रणनीतिक भंडार को मजबूत करने के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बनाना होगा।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Energy–economy linkage ● Policy examples ● Balanced conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> ● नवीकरणीय ऊर्जा का उल्लेख न करना ● केवल सिद्धांत लिखना, उदाहरण न देना

Case Study

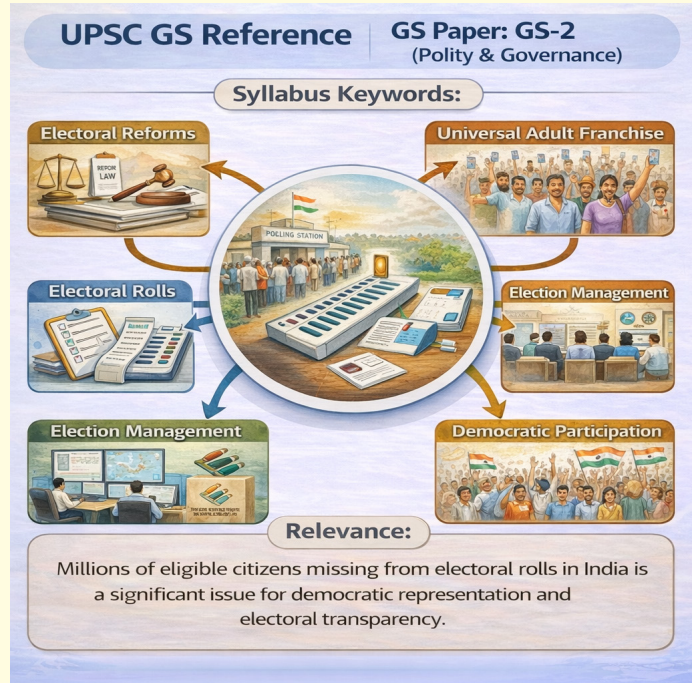
1. **1973 Oil Crisis** - तेल कीमतों के झटके से वैश्विक मंदी
2. **Russia–Ukraine War (2022)** - ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि
3. **India Strategic Petroleum Reserves Programme** - ऊर्जा सुरक्षा नीति

3 Millions of citizen non-voters!

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेखक का तर्क है कि चुनावी सूचियों से बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों का नाम गायब होना भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसे सुधारने के लिए संस्थागत उपाय आवश्यक हैं।

❖ **Author:** P.Chidambaram



Article Summary

भूमिका

भारत का लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) पर आधारित है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। किंतु हाल के वर्षों में यह चिंता सामने आई है कि बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के नाम चुनावी सूचियों से गायब हैं। पूर्व वित्त मंत्री P. Chidambaram के अनुसार देश की वयस्क आबादी का लगभग 10% औसतन मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। यदि ये लोग नागरिक और वयस्क हैं, तो उनका

नाम सूची में न होना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और चुनावी निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करता है। यह स्थिति चुनाव प्रबंधन और मतदाता पंजीकरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मुख्य भाग

लेख का पहला महत्वपूर्ण पहलू भारतीय लोकतंत्र में चुनावी संस्थाओं की भूमिका से जुड़ा है। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक भारत में चुनाव प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और व्यापक रूप से स्वीकार्य रही। आम नागरिकों के लिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, नियम और संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी सीमित थी, फिर भी चुनाव नियमित रूप से होते रहे और परिणामों को व्यापक स्वीकार्यता मिली। संविधान के भाग XV में चुनाव संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, जो चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू चुनावी सूचियों की सटीकता से जुड़ा है। मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव का आधार होती है क्योंकि उसी के आधार पर नागरिक अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अधूरा रह जाता है। लेखक के अनुसार भारत में वयस्क आबादी का लगभग 10% हिस्सा मतदाता सूची से बाहर है। ये लोग वयस्क हैं और नागरिक भी हैं, इसलिए उनका नाम सूची में न होना प्रशासनिक या प्रक्रियागत समस्याओं की ओर संकेत करता है।

Which aspect of electoral integrity is more critical for Indian democracy?



Electoral Institutions

1 Historically, electoral institutions have ensured regular elections and broad acceptance of results, even with limited public awareness of their workings.

The "चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, नियम और संवैधानिक प्रावधानों" were not widely known, yet elections were conducted and accepted.

2 While procedural simplicity was a feature, the text implies a potential for systemic issues if institutions are not robust.

The text focuses on the historical acceptance rather than direct negative impacts of institutional flaws.

3 The Constitution, specifically "भाग XV", grants the Election Commission the responsibility to conduct free and fair elections.

The "संविधान के भाग XV" outlines the mandate for electoral bodies.



Electoral Rolls

1 Electoral rolls are fundamental as they determine who can exercise their voting rights, directly impacting the completeness of democratic representation.

If a large number of eligible citizens are excluded, "लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अधूरा रह जाता है".

2 The exclusion of approximately 10% of the adult population from voter lists indicates significant administrative or procedural problems.

लगभग 10% हिस्सा मतदाता सूची से बाहर है" points to "प्रशासनिक या प्रक्रियागत समस्याओं".

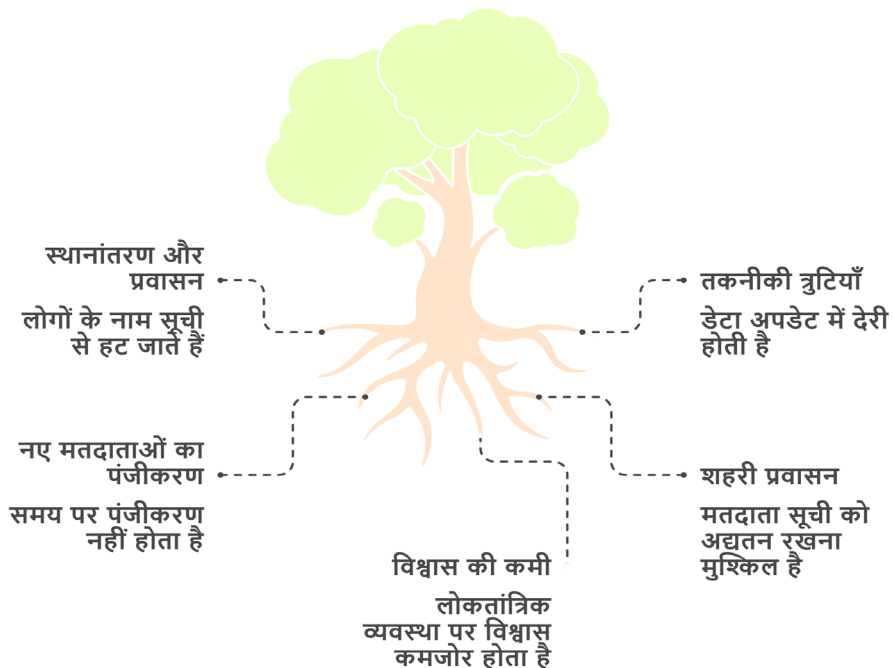
3 While not explicitly stated as a constitutional mandate for the rolls themselves, their accuracy is implied as essential for the functioning of the constitutional provisions for elections.

The text highlights the consequence of inaccurate rolls on democratic representation, which is a constitutional ideal.

तीसरा पहलू मतदाता पंजीकरण और चुनावी प्रक्रियाओं में आने वाली चुनौतियों का है। कई बार लोगों के नाम स्थानांतरण, प्रवासन, तकनीकी त्रुटियों या डेटा अपडेट में देरी के कारण सूची से हट जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नए मतदाताओं का पंजीकरण समय पर न होना भी समस्या को बढ़ाता है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लगातार प्रवासन और जनसंख्या परिवर्तन के कारण मतदाता सूची को अद्यतन रखना एक चुनौती बन जाता है। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सीमित हो सकती है।

चौथा पहलू लोकतंत्र की वैधता और विश्वास से जुड़ा है। चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि नागरिकों के विश्वास का भी प्रतीक होते हैं। यदि नागरिकों को लगता है कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या मतदान का अवसर नहीं मिल रहा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनका विश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और व्यापक मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करे।

मतदाता सूची अद्यतन में देरी से लोकतांत्रिक भागीदारी सीमित होती है



निष्कर्ष

चुनावी सूची से बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों का नाम गायब होना भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है जब प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर मिले। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर मतदाता सूची की नियमित समीक्षा, तकनीकी सुधार और व्यापक पंजीकरण अभियान चलाएँ। साथ ही नागरिकों में भी अपने नाम की जांच और पंजीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। यदि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे, तो भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और मजबूती और अधिक बढ़ेगी।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> • Context : चुनावी सूचियों से बड़ी संख्या में नागरिकों का नाम गायब • Core claim : यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है • Reason-1 : पात्र नागरिक मतदान से वंचित हो जाते हैं • Reason-2 : चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कम हो सकता है • Trade-off : प्रशासनिक चुनौतियाँ बनाम लोकतांत्रिक समावेशन • Way forward : बेहतर पंजीकरण प्रणाली और तकनीकी सुधार 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लेखक के अनुसार भारत की वयस्क आबादी का औसतन लगभग 10% हिस्सा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। 2. चुनाव संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग XV में निहित हैं। 3. कई नागरिकों के नाम प्रवासन, प्रशासनिक त्रुटियों या अद्यतन की कमी के कारण सूची से बाहर रह जाते हैं।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ लोग तर्क देते हैं कि मतदाता सूची से नाम गायब होना मुख्यतः प्रशासनिक या तकनीकी समस्या है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यह तर्क सीमित है क्योंकि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक का मतदान अधिकार महत्वपूर्ण है। यदि बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित रह जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस समस्या को केवल तकनीकी त्रुटि मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Universal Adult Franchise Electoral Roll Revision 	<ol style="list-style-type: none"> Electoral Roll <ul style="list-style-type: none"> Definition: किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची। Example: मतदान करने के लिए मतदाता का नाम निर्वाचन सूची में होना आवश्यक है। Universal Adult Franchise <ul style="list-style-type: none"> Definition: 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार। Example: भारत में 1950 से यह सिद्धांत लागू है।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Booth Level Officers (BLO) system ● Voter awareness programmes ● Electoral reforms and transparency ● Digital voter registration initiatives 	<p>3. Booth Level Officer (BLO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: चुनाव आयोग का स्थानीय अधिकारी जो मतदाता सूची के अद्यतन और सत्यापन का कार्य करता है। ● Example: BLO घर-घर जाकर मतदाता विवरण की पुष्टि करता है। <p>4. Electoral Integrity</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता। ● Example: सटीक मतदाता सूची चुनावी अखंडता सुनिश्चित करती है। <p>5. SVEEP Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: चुनाव आयोग का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। ● Example: SVEEP के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

भारतीय लोकतंत्र में सटीक और समावेशी मतदाता सूची का महत्व स्पष्ट कीजिए।

Keywords: Electoral rolls, Democratic participation, Universal franchise, Election Commission, Voter registration, Electoral integrity

Model Answer Draft

Introduction:

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में समान और निष्पक्ष अवसर मिले। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए सटीक और समावेशी मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है।

Body:

सबसे पहले, मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का आधार है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह मतदान के अधिकार से वंचित हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी कम हो सकती है।

दूसरा, सटीक मतदाता सूची चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यदि सूची में त्रुटियाँ हों या पात्र मतदाता शामिल न हों, तो चुनावी परिणामों की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

तीसरा, समावेशी मतदाता सूची सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता को भी बढ़ावा देती है। जब सभी वर्गों के नागरिक मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो लोकतांत्रिक निर्णय अधिक प्रतिनिधिक बनते हैं।

Conclusion:

इस प्रकार सटीक और समावेशी मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके लिए चुनाव आयोग को नियमित अद्यतन, तकनीकी सुधार और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Universal franchise link • Democratic legitimacy • Institutional reforms 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करना • मतदाता सूची के महत्व को उदाहरण से न समझाना

प्रश्न:-2

भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदाता पंजीकरण से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: Voter registration, Migration, Electoral roll errors, Digital governance, Election Commission reforms

Model Answer Draft

Introduction:

मतदाता पंजीकरण किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की मूलभूत प्रक्रिया है क्योंकि इसके माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

Body:

पहली चुनौती प्रवासन और जनसंख्या परिवर्तन है। शहरीकरण और रोजगार के कारण लोग लगातार स्थान बदलते रहते हैं, जिससे मतदाता सूची को अद्यतन करना कठिन हो जाता है।

दूसरी चुनौती प्रशासनिक और तकनीकी त्रुटियाँ हैं। कई बार डेटा प्रविष्टि की गलतियाँ या अद्यतन में देरी के कारण पात्र नागरिकों के नाम सूची से हट जाते हैं।

तीसरी चुनौती मतदाता जागरूकता की कमी है। कई नागरिक समय पर अपने नाम की जांच या पंजीकरण नहीं कराते, जिससे वे मतदान से वंचित रह जाते हैं।

Conclusion:

इन चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रणाली, नियमित सूची संशोधन और व्यापक जागरूकता अभियान आवश्यक हैं। यदि चुनाव आयोग इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करे, तो मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी बन सकती है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Practical challenges ● Governance reforms ● Technology role 	<ul style="list-style-type: none"> ● केवल समस्या बताना, समाधान न देना ● चुनाव आयोग की भूमिका का उल्लेख न करना

Case Study

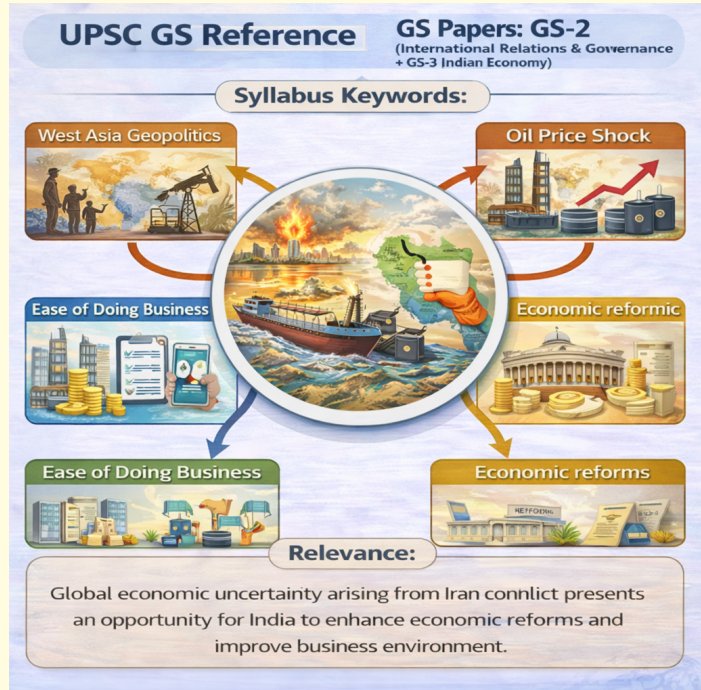
1. **Electoral Roll Purification Programme** - मतदाता सूची की शुद्धता के लिए अभियान
2. **SVEEP Programme (Systematic Voters' Education and Electoral Participation)** - मतदाता जागरूकता कार्यक्रम
3. **Online Voter Registration Portal** - डिजिटल पंजीकरण प्रणाली

4 Why the war in Iran gives India a chance to put its own house in order

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेखिका का तर्क है कि ईरान युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट भारत के लिए अपनी आर्थिक और प्रशासनिक कमजोरियों को सुधारने का अवसर है।

❖ Author: Tavleen Singh



Article Summary

भूमिका

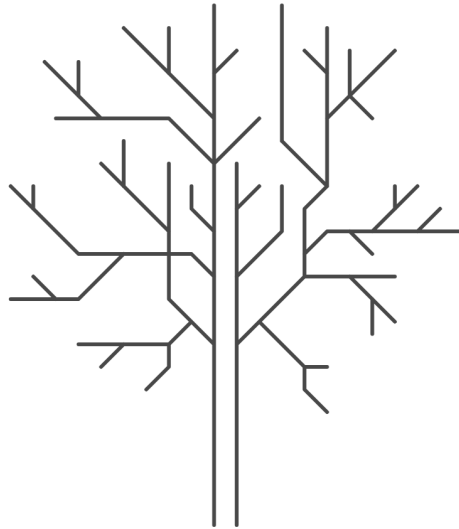
पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष केवल क्षेत्रीय राजनीतिक संकट नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का कारण भी बन रहा है। विशेष रूप से ईरान से जुड़े युद्ध ने तेल कीमतों में तेज वृद्धि और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। हालांकि, स्तंभकार Tavleen Singh का मानना है कि यह

संकट भारत के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है। यदि भारत अपनी आर्थिक नीतियों, प्रशासनिक ढांचे और व्यापारिक वातावरण में सुधार करे, तो वह बाहरी संकटों के प्रभाव को कम कर सकता है।

मुख्य भाग

लेख का पहला महत्वपूर्ण पहलू पश्चिम एशिया युद्ध के मानवीय और राजनीतिक आयाम से जुड़ा है। लेखिका ने ईरान की राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि वहां की शासन व्यवस्था लंबे समय से दमनकारी रही है। हाल के वर्षों में सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और उनके दमन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। ऐसे घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव किसी देश को राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव से जुड़ा है। ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। लेख में यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो तेल कीमतें और बढ़ सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल कीमतों में वृद्धि से महँगाई, चालू खाते के घाटे और आर्थिक वृद्धि पर दबाव पड़ सकता है।



पश्चिम एशिया युद्ध के कारण भारत पर बहुआयामी प्रभाव



वैश्विक अर्थव्यवस्था

तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है



ईरान की राजनीतिक व्यवस्था

दमनकारी शासन अस्थिरता को बढ़ावा देता है

तीसरा पहलू भारत की आंतरिक आर्थिक संरचना से संबंधित है। लेखिका का मानना है कि भारत को केवल बाहरी संकटों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने घरेलू आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से Ease of Doing Business के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। नौकरशाही जटिलताएँ, नियामकीय बाधाएँ और प्रशासनिक देरी निवेश और उद्यमिता को प्रभावित करती हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीली बन सकती है।

चौथा महत्वपूर्ण पहलू नीति-निर्माण और शासन से जुड़ा है। लेखिका का तर्क है कि प्रधानमंत्री और नीति-निर्माताओं को यह समझना चाहिए कि केवल नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक सुधार तब संभव होंगे जब प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास भी तेज हो सकता है।

घरेलू आर्थिक सुधार भारत को मजबूत करते हैं



निष्कर्ष

ईरान युद्ध जैसी वैश्विक घटनाएँ अक्सर आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करती हैं, लेकिन वे नीति सुधार के अवसर भी प्रदान करती हैं। भारत के लिए यह समय अपनी आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने का है। यदि सरकार व्यवसायिक वातावरण को बेहतर बनाने, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल करने और आर्थिक सुधारों को तेज करने पर ध्यान दे, तो भारत बाहरी संकटों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकता है। इस प्रकार वैश्विक संकट को अवसर में बदलकर भारत अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास क्षमता को मजबूत कर सकता है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : ईरान युद्ध और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ● Core claim : भारत को इस संकट को आर्थिक सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए ● Reason-1 : तेल कीमतों में वृद्धि से आर्थिक दबाव ● Reason-2 : घरेलू प्रशासनिक और व्यापारिक बाधाएँ ● Trade-off : वैश्विक संकट बनाम घरेलू सुधार का अवसर ● Way forward : Ease of Doing Business सुधार और आर्थिक नीतियों का सरलीकरण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ईरान युद्ध के शुरुआती तीन सप्ताहों में तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। 2. युद्ध लंबा खिंचने पर तेल कीमतों में और वृद्धि की आशंका जताई गई है। 3. लेखिका के अनुसार भारत में अभी भी व्यापार करना कई कारणों से कठिन बना हुआ है।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक संकटों के दौरान घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है क्योंकि सरकार का ध्यान तात्कालिक आर्थिक स्थिरता पर रहता है। हालांकि यह दृष्टिकोण सीमित है, क्योंकि संकट के समय ही संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता अधिक स्पष्ट होती है। यदि भारत इस अवसर का उपयोग सुधारों के लिए करता है, तो भविष्य के बाहरी झटकों के प्रति उसकी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बन सकती है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Ease of Doing Business reforms 	<p>1. Ease of Doing Business</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: किसी देश में व्यवसाय शुरू करने और चलाने की सरलता का सूचकांक। Example: सरल लाइसेंस और कर प्रणाली से Ease of Doing Business बेहतर होता है।
<ul style="list-style-type: none"> Energy import dependency 	<p>2. Oil Price Shock</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में अचानक वृद्धि। Example: पश्चिम एशिया युद्ध के कारण तेल कीमतों में तेजी।
<ul style="list-style-type: none"> Oil price shocks and inflation 	<p>3. Economic Resilience</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: किसी अर्थव्यवस्था की संकटों से उबरने की क्षमता। Example: विविधीकृत ऊर्जा स्रोत आर्थिक लचीलापन बढ़ाते हैं।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Governance and regulatory reforms ● Economic resilience ● Structural economic reforms 	<p>4. Structural Reforms</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे में सुधार करने वाली नीतियाँ। ● Example: 1991 के आर्थिक सुधार। <p>5. Energy Security</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की निरंतर और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना। ● Example: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:-1

वैश्विक भू-राजनीतिक संकट भारत के लिए आर्थिक सुधारों के अवसर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? विश्लेषण कीजिए।

Keywords: Geopolitical crisis, Economic reforms, Oil shocks, Governance, Economic resilience, Policy reforms

Model Answer Draft

Introduction:

वैश्विक भू-राजनीतिक संकट अक्सर आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करते हैं, किंतु वे देशों को अपनी नीतियों और संस्थागत ढांचे की समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए ऐसे संकट आर्थिक सुधारों को तेज करने की प्रेरणा बन सकते हैं।

Body:

सबसे पहले, वैश्विक संकट आर्थिक कमजोरियों को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, तेल कीमतों में वृद्धि भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को सामने लाती है। इससे नीति-निर्माताओं को ऊर्जा विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता का एहसास होता है।

दूसरा, संकट प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधारों के लिए दबाव उत्पन्न करते हैं। जब वैश्विक आर्थिक वातावरण चुनौतीपूर्ण होता है, तो निवेश आकर्षित करने के लिए देशों को अपने व्यापारिक वातावरण को अधिक अनुकूल बनाना पड़ता है।

तीसरा, ऐसे समय में आर्थिक नीतियों को अधिक लचीला और दूरदर्शी बनाना आवश्यक हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति अधिक मजबूत बन सकती है।

Conclusion:

इस प्रकार वैश्विक संकट केवल चुनौतियाँ ही नहीं बल्कि सुधार के अवसर भी प्रदान करते हैं। यदि भारत इन अवसरों का उपयोग संरचनात्मक सुधारों और आर्थिक विविधीकरण के लिए करे, तो वह भविष्य के संकटों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकता है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Crisis as catalyst for reform ● Historical example (1991 reforms) ● Policy suggestions 	<ul style="list-style-type: none"> ● केवल संकट का वर्णन करना ● सुधारों का स्पष्ट उल्लेख न करना

प्रश्न:-2

भारत में **Ease of Doing Business** सुधारों का आर्थिक विकास में क्या महत्व है?

Keywords: Ease of Doing Business, Investment climate, Regulatory reforms, Economic growth, Entrepreneurship

Model Answer Draft

Introduction:

आर्थिक विकास के लिए निवेश, उद्यमिता और उद्योगों का विस्तार आवश्यक होता है। इन सभी के लिए अनुकूल व्यापारिक वातावरण जरूरी है, जिसे Ease of Doing Business के माध्यम से मापा जाता है।

Body:

पहला पहलू यह है कि बेहतर व्यापारिक वातावरण विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करता है। जब नियामकीय प्रक्रियाएँ सरल और पारदर्शी होती हैं, तो उद्योगों की स्थापना और संचालन आसान हो जाता है।

दूसरा पहलू उद्यमिता और रोजगार सृजन से जुड़ा है। यदि व्यवसाय शुरू करना आसान हो, तो नए उद्यम और स्टार्टअप तेजी से विकसित होते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

तीसरा पहलू वैश्विक प्रतिस्पर्धा का है। बेहतर Ease of Doing Business रैंकिंग से देश की वैश्विक छवि मजबूत होती है और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।

Conclusion:

इस प्रकार Ease of Doing Business सुधार आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और नियामकीय बाधाओं को कम करके इस दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> Investment + entrepreneurship link Governance reforms mention Balanced conclusion 	<ul style="list-style-type: none"> केवल रैंकिंग का उल्लेख करना नीति सुधारों के उदाहरण न देना

Case Study

- 1991 Economic Reforms in India** - आर्थिक संकट के दौरान संरचनात्मक सुधार
- Russia-Ukraine War (2022)** - ऊर्जा संकट का वैश्विक प्रभाव
- Make in India Initiative** - निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति

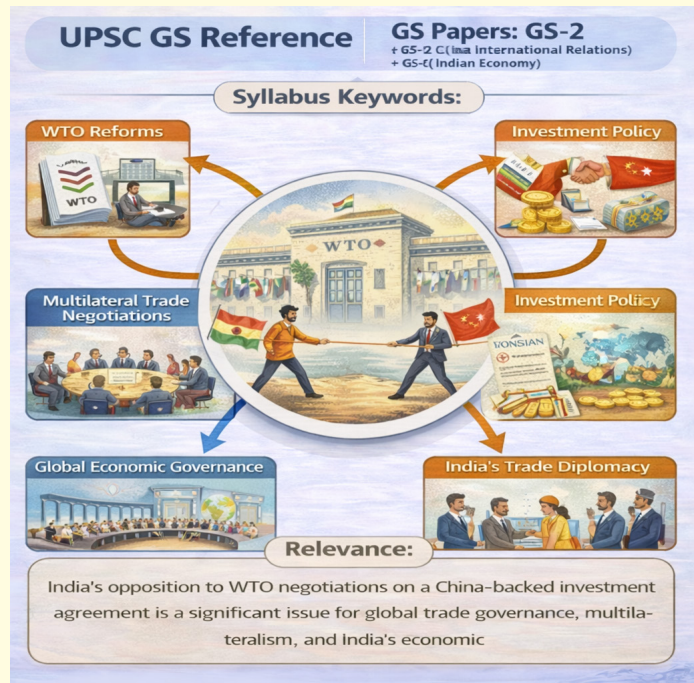
5

India is opposing a China-led WTO investment deal, even at the risk of isolation. Here's why

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेख का तर्क है कि भारत WTO में निवेश समझौते का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि यह बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था और विकासशील देशों के हितों के लिए दीर्घकालिक जोखिम पैदा कर सकता है।

❖ **Author:** Ravi Dutta Mishra



Article Summary

भूमिका

वैश्विक व्यापार व्यवस्था में World Trade Organization (WTO) की भूमिका नियम-आधारित व्यापार प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है। हाल के वर्षों में चीन समर्थित Investment Facilitation for Development (IFD) Agreement पर बहस तेज हो गई है, जिसका उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाना बताया जा रहा है। हालांकि 2017 में 70 देशों से बढ़कर 2025 तक 128 देशों का समर्थन मिलने के बावजूद भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों

ने इसका विरोध किया है। भारत का मानना है कि इस समझौते को WTO में शामिल करने का प्रस्ताव बहुपक्षीय प्रणाली की मूल संरचना को प्रभावित कर सकता है और विकासशील देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

मुख्य भाग

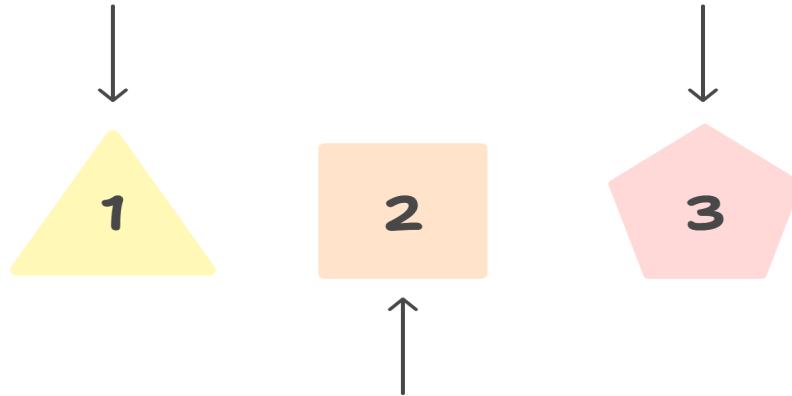
पहला महत्वपूर्ण पहलू इस निवेश समझौते की प्रकृति और उद्देश्य से जुड़ा है। Investment Facilitation for Development (IFD) Agreement का मुख्य उद्देश्य देशों में निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है। समर्थकों का तर्क है कि इससे विकासशील देशों में विदेशी निवेश आकर्षित होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यही कारण है कि 2017 में जब इस समझौते पर चर्चा शुरू हुई थी तब लगभग 70 देशों का समर्थन था, जो बाद में बढ़कर 128 देशों तक पहुँच गया।

दूसरा पहलू भारत के विरोध के कारणों से संबंधित है। भारत का तर्क है कि इस समझौते को plurilateral route के माध्यम से WTO ढांचे में शामिल करना संगठन की बहुपक्षीय प्रकृति को कमजोर कर सकता है। WTO की मूल अवधारणा यह है कि सभी सदस्य देशों की सहमति से नियम बनाए जाएँ। यदि कुछ देशों का समूह अलग से समझौता बनाकर उसे संगठन के ढांचे में शामिल करता है, तो इससे WTO के निर्णय लेने की प्रक्रिया और संतुलन प्रभावित हो सकता है।

निवेश समझौते का विकास

प्रारंभिक चर्चा
२० देशों का समर्थन

भारत का विरोध
बहुपक्षीय प्रकृति को
कमजोर करना



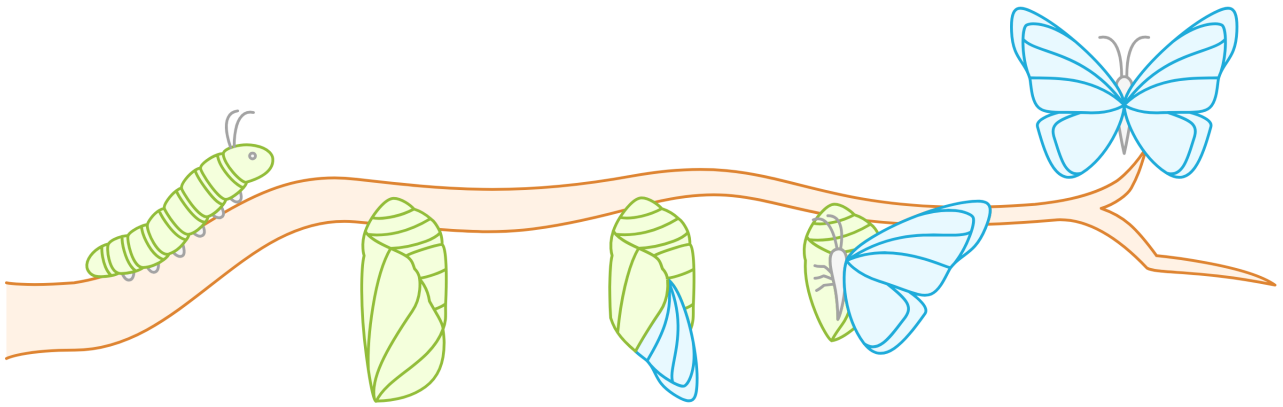
समर्थन में वृद्धि
१२४ देशों तक पहुँचा

तीसरा पहलू वैश्विक व्यापार व्यवस्था में उभरती चुनौतियों का है। हाल के वर्षों में कई देशों द्वारा लगाए गए संरक्षणवादी उपायों और व्यापारिक टैरिफ ने WTO की भूमिका पर प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में अनिश्चितता बढ़ाई है। ऐसी स्थिति में भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि WTO की संस्थागत संरचना कमजोर न हो और विकासशील देशों की आवाज़ को पर्याप्त महत्व मिले।

चौथा पहलू भारत की रणनीतिक और आर्थिक कूटनीति से जुड़ा है। भारत का मानना है कि निवेश से जुड़े मुद्दे पहले से ही विभिन्न द्विपक्षीय निवेश समझौतों और घरेलू नीतियों के माध्यम से प्रबंधित किए जा सकते हैं। यदि IFD जैसे समझौते को WTO के ढांचे में शामिल किया जाता है, तो इससे भविष्य में नए दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं जो नीति-निर्माण की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इसलिए

भारत ने दीर्घकालिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है, भले ही इससे उसे कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अलगाव का सामना करना पड़े।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की भूमिका



संरक्षणवादी
उपाय
व्यापारिक टैरिफ और
अनिश्चितता

WTO की भूमिका
संस्थागत संरचना को
मजबूत करना

विकासशील देशों
की आवाज़
पर्याप्त महत्व सुनिश्चित
करना

रणनीतिक
कूटनीति
द्विपक्षीय समझौतों का
उपयोग

दीर्घकालिक
आर्थिक हित
नीति-निर्माण की
स्वतंत्रता

निष्कर्ष

WTO में निवेश समझौते पर भारत का रुख यह दर्शाता है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में राष्ट्रीय हित और बहुपक्षीय नियमों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि IFD समझौते को कई देशों का समर्थन प्राप्त है, भारत का मानना है कि इसे WTO ढांचे में शामिल करने से संगठन की मूल बहुपक्षीय प्रकृति प्रभावित हो सकती है। दीर्घकालिक दृष्टि से भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार नियम समावेशी, संतुलित और विकासशील देशों के हितों के अनुकूल हों। इसलिए यह मुद्दा केवल एक निवेश समझौते का नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक शासन के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : WTO में चीन-समर्थित निवेश समझौते पर बहस ● Core claim : भारत plurilateral समझौते के माध्यम से इसे शामिल करने का विरोध कर रहा है ● Reason-1 : WTO की बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रिया कमजोर हो सकती है ● Reason-2 : भविष्य में नीति-निर्माण की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है ● Trade-off : वैश्विक निवेश सुविधा बनाम संस्थागत संतुलन ● Way forward : WTO सुधार और विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IFD समझौते के समर्थन में देशों की संख्या 2017 में 70 से बढ़कर 128 हो गई। 2. WTO के कुल 166 सदस्य देशों में से अधिकांश इस समझौते का समर्थन कर रहे हैं। 3. भारत और दक्षिण अफ्रीका इस प्रस्ताव के प्रमुख विरोधियों में शामिल हैं।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

समर्थकों का तर्क है कि IFD समझौता निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा दे सकता है। छोटे और संसाधन-सीमित देशों के लिए यह समझौता निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। हालांकि भारत का मानना है कि इस समझौते को WTO के ढांचे में शामिल करने से बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रिया कमजोर हो सकती है और दीर्घकालिक संस्थागत संतुलन प्रभावित हो सकता है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> WTO Marrakesh Agreement (1995) 	<p>1. Plurilateral Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: सीमित देशों के समूह के बीच किया गया अंतरराष्ट्रीय समझौता। Example: WTO में कुछ सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित IFD Agreement।
<ul style="list-style-type: none"> Plurilateral vs Multilateral agreements 	<p>2. Multilateral Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: ऐसा समझौता जिसमें सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। Example: WTO के अधिकांश व्यापार नियम बहुपक्षीय समझौतों पर आधारित हैं।
<ul style="list-style-type: none"> Investment facilitation vs investment protection 	<p>3. Investment Facilitation</p> <ul style="list-style-type: none"> Definition: निवेश प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की नीति। Example: प्रशासनिक बाधाओं को कम करना निवेश सुविधा का हिस्सा है।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Trade governance reforms ● Global South interests in trade negotiations ● India–South Africa coordination in WTO 	<p>4. Marrakesh Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: 1995 में हस्ताक्षरित समझौता जिसने WTO की स्थापना की। ● Example: WTO के संस्थागत ढांचे की आधारशिला Marrakesh Agreement है। <p>5. Trade Diplomacy</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definition: अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की रणनीति। ● Example: WTO में भारत का रुख उसकी व्यापार कूटनीति को दर्शाता है।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय और बहु-पक्षीय (plurilateral) समझौतों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और उनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: WTO, Multilateralism, Plurilateral agreements, Trade governance, Global negotiations, Developing countries

Model Answer Draft

Introduction:

वैश्विक व्यापार व्यवस्था मुख्यतः नियम-आधारित बहुपक्षीय प्रणाली पर आधारित है, जिसका संचालन World Trade Organization द्वारा किया जाता है। WTO के तहत अधिकांश व्यापार नियम सभी सदस्य देशों की सहमति से बनाए जाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में plurilateral समझौतों की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिनमें केवल इच्छुक देशों का समूह भाग लेता है।

Body:

बहुपक्षीय (Multilateral) समझौते वे होते हैं जिनमें WTO के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। इनका उद्देश्य वैश्विक व्यापार नियमों में समानता और संतुलन बनाए रखना होता है।

इसके विपरीत Plurilateral समझौते सीमित संख्या में देशों के बीच होते हैं। ये समझौते तेज निर्णय लेने और विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

हालांकि plurilateral समझौतों से कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। पहला, इससे WTO की समावेशी निर्णय प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। दूसरा, छोटे और विकासशील देशों पर नए नियमों को स्वीकार करने का दबाव बढ़ सकता है।

फिर भी समर्थकों का तर्क है कि जब बहुपक्षीय वार्ताएँ लंबे समय तक गतिरोध में रहती हैं, तब plurilateral समझौते प्रगति का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं।

Conclusion:

अतः बहुपक्षीय और plurilateral समझौतों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। WTO को ऐसे समाधान विकसित करने चाहिए जो समावेशिता बनाए रखते हुए वैश्विक व्यापार सहयोग को आगे बढ़ा सकें।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Multilateral vs plurilateral comparison • WTO governance reference • Balanced evaluation 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल परिभाषा देना, विश्लेषण न करना • उदाहरण या प्रभावों का उल्लेख न करना

प्रश्न:-2

WTO में भारत की व्यापार कूटनीति के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: Trade diplomacy, WTO negotiations, Developing country interests, Policy autonomy, Global trade rules

Model Answer Draft

Introduction:

भारत की व्यापार कूटनीति का उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रणाली में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास हितों और नीति-निर्माण की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। WTO में भारत का रुख अक्सर विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा पर केंद्रित रहा है।

Body:

भारत की व्यापार कूटनीति का पहला सिद्धांत बहुपक्षीयता का समर्थन है। भारत चाहता है कि वैश्विक व्यापार नियम सभी सदस्य देशों की सहमति से तय हों ताकि छोटे और विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सके।

दूसरा सिद्धांत नीति-निर्माण की स्वायत्तता है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते उसकी घरेलू आर्थिक नीतियों और विकास कार्यक्रमों को सीमित न करें।

तीसरा सिद्धांत विकासशील देशों के हितों की रक्षा है। भारत अक्सर कृषि सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा और निवेश नियमों जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करता रहा है।

Conclusion:

इस प्रकार भारत की व्यापार कूटनीति संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें वैश्विक व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और नीति स्वायत्तता को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> Trade diplomacy principles Developing country perspective Policy autonomy concept 	<ul style="list-style-type: none"> WTO का सामान्य विवरण लिखना भारत की विशिष्ट रणनीति का उल्लेख न करना

Case Study

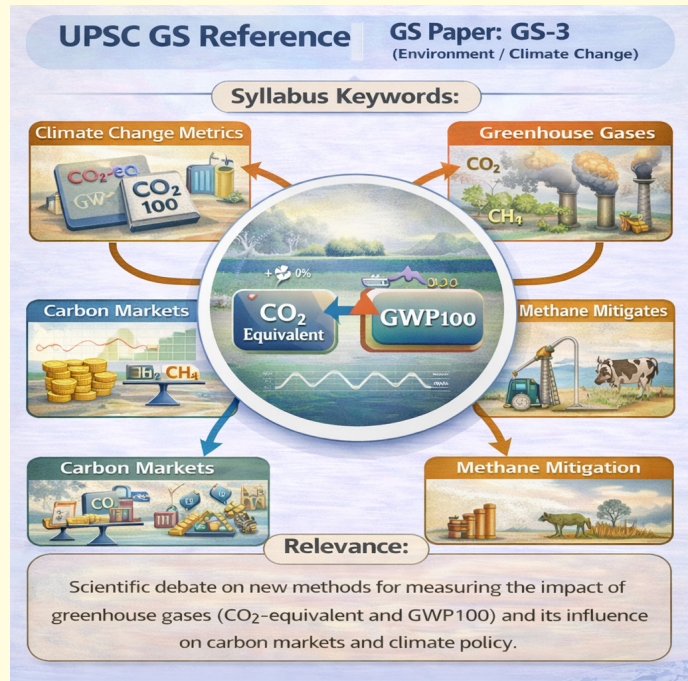
- WTO Doha Development Round** - विकासशील देशों के हितों पर बहस
- India's Bilateral Investment Treaties (BITs)** - निवेश संरक्षण ढांचा
- Trade disputes at WTO** - वैश्विक व्यापार नियमों का अनुपालन

6 Are we measuring global warming wrong: What a new study says

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेखकों का तर्क है कि वर्तमान GWP100-आधारित कार्बन गणना प्रणाली ग्रीनहाउस गैसों के वास्तविक जलवायु प्रभाव को सही ढंग से नहीं दर्शाती, इसलिए अधिक वैज्ञानिक और समय-संवेदनशील पद्धति की आवश्यकता है।

❖ **Author:** Durwood Zaelke, Zerin Osho



Article Summary

भूमिका

वैश्विक जलवायु नीति में विभिन्न ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव की तुलना करने के लिए Carbon Dioxide Equivalent (CO₂e) का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली Global Warming Potential (GWP100) नामक मापदंड पर आधारित है, जो किसी गैस के प्रभाव को 100 वर्षों की अवधि में मापता है। हालांकि हाल के एक अध्ययन में यह तर्क दिया गया है कि यह पद्धति सभी गैसों के वास्तविक जलवायु प्रभाव को समान रूप से नहीं दर्शाती। विशेष रूप से मीथेन जैसी अल्प-

जीवी लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली गैसों का प्रभाव कम आंका जा सकता है। अध्ययन ने एक नया ढांचा Radiative Forcing-based Accounting (RFA) प्रस्तावित किया है, जो गैसों के वास्तविक प्रभाव और समय-आधारित बदलाव को बेहतर ढंग से मापने का प्रयास करता है।

मुख्य भाग

(1) वर्तमान प्रणाली: CO₂-Equivalent और GWP100

जलवायु नीति में विभिन्न गैसों के प्रभाव की तुलना करने के लिए CO₂ को आधार माना जाता है।

अन्य गैसों को CO₂-equivalent (CO₂e) में बदलने के लिए Global Warming Potential (GWP) का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए:

- Methane का GWP100 लगभग 28 है।
- इसका अर्थ है कि 1 टन मीथेन = 28 टन CO₂ के बराबर प्रभाव (100 वर्षों में)।

यह प्रणाली पिछले 30 वर्षों से वैश्विक जलवायु नीति का आधार रही है।

(2) समस्या: अलग-अलग गैसों का अलग व्यवहार

ग्रीनहाउस गैसों वातावरण में अलग-अलग तरीके से व्यवहार करती हैं।

Carbon dioxide

- अपेक्षाकृत कम तीव्र प्रभाव
- लेकिन वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बनी रहती है

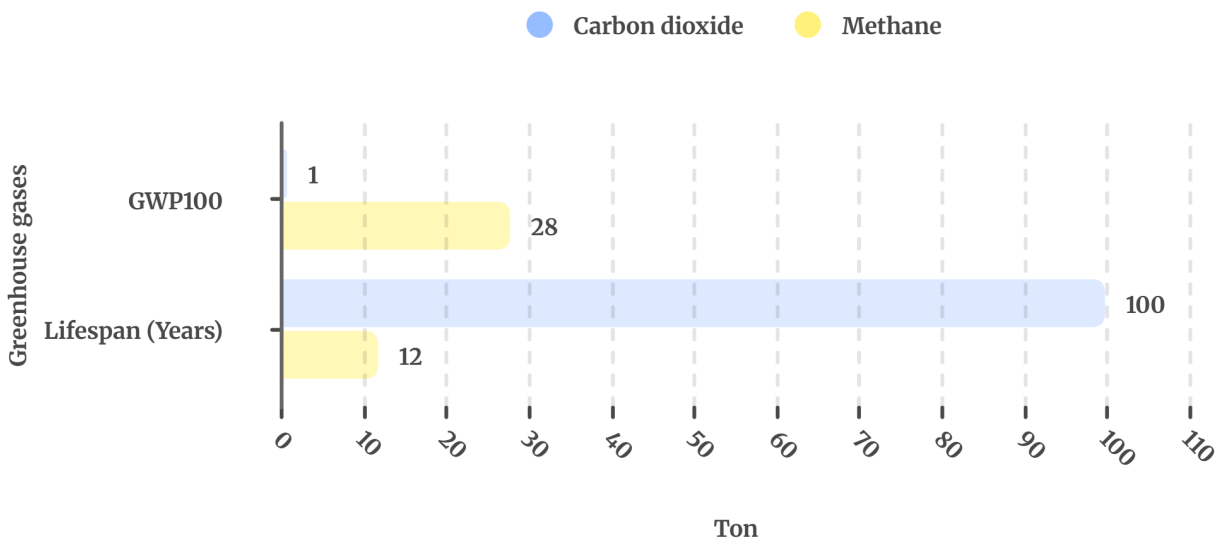
Methane

- बहुत अधिक शक्तिशाली
- लेकिन लगभग 12 वर्ष में समाप्त हो जाती है

GWP100 इन दोनों गैसों के प्रभाव को 100 वर्षों में औसत करके दिखाता है। इससे मीथेन के अल्पकालिक प्रभाव का महत्व कम दिखाई देता है।

Comparative analysis of greenhouse gases

Methane's GWP100 is much higher than carbon dioxide, but its atmospheric lifespan is much shorter.



(3) मीथेन कटौती क्यों महत्वपूर्ण है

मीथेन उत्सर्जन को कम करना जलवायु परिवर्तन को जल्दी धीमा करने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है।

कारण:

- यह गैस अल्प-जीवी है
- कटौती का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है
- वैश्विक तापमान वृद्धि को निकट अवधि में कम किया जा सकता है

इसके बावजूद वर्तमान कार्बन बाजार प्रणाली में मीथेन परियोजनाओं को कम क्रेडिट मिल सकते हैं।

(4) नया प्रस्ताव: Radiative Forcing-based Accounting (RFA)

अध्ययन ने एक नया ढांचा प्रस्तावित किया है:

Radiative Forcing-based Accounting (RFA)

Radiative Forcing का अर्थ है:

पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में आने वाली सौर ऊर्जा और बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच अंतर।

RFA प्रणाली में:

- गैस की ऊष्मा फँसाने की क्षमता (radiative efficiency)
- गैस का वायुमंडलीय जीवनकाल (atmospheric lifetime)
- समय के साथ बदलता प्रभाव

इन सभी को ध्यान में रखा जाता है।

मीथेन कटौती के लाभ और RFA का अनावरण



(5) GWP100 और RFA में अंतर

पहलू	GWP100	RFA
प्रकृति	Static	Dynamic
समय	100 वर्ष का स्थिर औसत	समय के साथ बदलता प्रभाव
गैस व्यवहार	सरल तुलना	वास्तविक वातावरणीय व्यवहार
नीति प्रभाव	दीर्घकालिक औसत	अल्पकालिक जलवायु लाभ भी दिखाता

इस प्रकार RFA प्रणाली समय-संवेदनशील जलवायु कार्रवाई को बेहतर ढंग से दर्शाती है।

(6) अध्ययन के परिणाम

अध्ययन में कई मीथेन-कटौती परियोजनाओं का विश्लेषण किया गया, जैसे:

- लैंडफिल गैस परियोजना – चीन
- कचरा प्रबंधन परियोजना – चंडीगढ़
- औद्योगिक अपशिष्ट जल परियोजना – तमिलनाडु
- पशुधन अपशिष्ट परियोजना – ब्राजील

इन परियोजनाओं पर RFA लागू करने पर पाया गया कि:

वर्तमान प्रणाली की तुलना में मीथेन परियोजनाओं को 36-40% कम क्रेडिट मिल रहे थे।

(7) कार्बन बाजार पर प्रभाव

कार्बन बाजार में उत्सर्जन कटौती को वित्तीय मूल्य दिया जाता है।

यदि गणना प्रणाली गलत है तो:

- कुछ परियोजनाओं को कम वित्तीय समर्थन मिलेगा
- जलवायु लाभ कम आंका जाएगा
- निवेश का दिशा-निर्देशन गलत हो सकता है

इसलिए गणना पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल उत्सर्जन कम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें मापने की पद्धति भी वैज्ञानिक और यथार्थवादी होनी चाहिए। वर्तमान GWP100-आधारित प्रणाली ने वैश्विक नीति को सरल बनाया है, लेकिन यह सभी गैसों के प्रभाव को समान रूप से नहीं दर्शाती। प्रस्तावित Radiative Forcing-based Accounting (RFA) गैसों के वास्तविक वातावरणीय व्यवहार और समय-आधारित प्रभाव को बेहतर ढंग से दर्शाने का प्रयास करता है। यदि भविष्य में इस तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, तो कार्बन बाजार अधिक प्रभावी बन सकते हैं और जलवायु कार्रवाई को तेज किया जा सकता है।

मुख्य विचार

1. मीथेन का GWP100 लगभग 28 है।
2. मीथेन का वातावरणीय जीवनकाल लगभग 12 वर्ष है।
3. अध्ययन के अनुसार वर्तमान प्रणाली मीथेन परियोजनाओं को 36–40% तक कम क्रेडिट दे सकती है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) रिपोर्टों में radiative forcing का उपयोग 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chandigarh Waste Diversion Project <ul style="list-style-type: none"> • कचरा प्रबंधन के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Kyoto Protocol के तहत Clean Development Mechanism ● Carbon markets और emission trading ● Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs) ● Methane mitigation strategies ● Climate accounting reforms 	<p>2. Landfill Gas Project (China)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लैंडफिल से निकलने वाली गैस को ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करना। <p>3. Industrial Wastewater Project (Tamil Nadu)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● औद्योगिक अपशिष्ट जल से मीथेन उत्सर्जन में कमी। <p>4. Livestock Manure Project (Brazil)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पशुधन अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को मापने की वर्तमान पद्धति (CO₂-equivalent और Global Warming Potential) की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। क्या नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ जलवायु नीति को अधिक प्रभावी बना सकती हैं?

Keywords: Climate metrics, Greenhouse gases, Methane emissions, Carbon accounting, Climate policy

Model Answer Draft

Introduction:

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को एक समान मापदंड में व्यक्त करना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से वैश्विक जलवायु नीति में Carbon Dioxide Equivalent (CO₂e) और Global Warming Potential (GWP) का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली मुख्यतः Intergovernmental Panel on Climate Change द्वारा विकसित वैज्ञानिक आकलनों पर आधारित है।

Body:

वर्तमान पद्धति (CO₂e और GWP100)

इस प्रणाली में कार्बन डाइऑक्साइड को आधार मानकर अन्य गैसों को CO₂-equivalent में बदला जाता है। उदाहरण के लिए मीथेन का GWP100 लगभग 28 है, जिसका अर्थ है कि 100 वर्षों में इसका प्रभाव CO₂ से 28 गुना अधिक माना जाता है।

मुख्य सीमाएँ

- समय-आधारित प्रभाव का अभाव:** GWP100 सभी गैसों के प्रभाव को 100 वर्षों में औसत कर देता है, जिससे अल्पकालिक प्रभाव स्पष्ट नहीं होता।
- गैसों के अलग-अलग व्यवहार की अनदेखी:** CO₂ सैकड़ों वर्षों तक रहती है, जबकि मीथेन लगभग 12 वर्षों में समाप्त हो जाती है।
- कार्बन बाजार पर प्रभाव:** इससे मीथेन जैसी गैसों को कम महत्व मिल सकता है और कुछ परियोजनाओं को कम क्रेडिट मिलते हैं।

नई पद्धतियाँ (जैसे Radiative Forcing-based Accounting)

ये पद्धतियाँ गैसों के वास्तविक वातावरणीय जीवनकाल और समय के साथ बदलते प्रभाव को ध्यान में रखती हैं, जिससे जलवायु नीति अधिक वैज्ञानिक और सटीक हो सकती है।

Conclusion:

अतः जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्सर्जन मापन की पद्धतियों को भी अद्यतन करना आवश्यक है, ताकि नीतियाँ वास्तविक जलवायु प्रभाव को सही ढंग से प्रतिबिंबित कर सकें।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • CO₂-equivalent concept • GWP100 limitation (100-year averaging) • Methane vs CO₂ comparison • Climate accounting reforms • Link with carbon markets 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल ग्रीनहाउस गैसों की सूची लिख देना • GWP100 की सीमाओं का विश्लेषण न करना • नीति और कार्बन बाजार से लिंक न जोड़ना • निष्कर्ष में समाधान न देना

प्रश्न:-2

मीथेन उत्सर्जन को कम करना जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक त्वरित उपाय क्यों माना जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

Keywords: Methane mitigation, Short-lived climate pollutants, Climate action, Carbon markets

Model Answer Draft

Introduction:

मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसका वातावरणीय जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है, फिर भी यह अल्प अवधि में अत्यधिक गर्मी को अवशोषित कर सकती है।

Body:

1. उच्च तापीय क्षमता

मीथेन की Global Warming Potential, CO₂ की तुलना में लगभग 28 गुना अधिक मानी जाती है।

2. अल्पकालिक जीवनकाल

यह लगभग 12 वर्षों तक वातावरण में रहती है। इसलिए इसकी कटौती का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है।

3. त्वरित जलवायु लाभ

मीथेन उत्सर्जन में कमी से निकट भविष्य में तापमान वृद्धि को धीमा किया जा सकता है।

4. प्रमुख स्रोत

- कृषि और पशुपालन
- लैंडफिल और कचरा प्रबंधन
- तेल और गैस उद्योग

5. परियोजनाओं के उदाहरण

- लैंडफिल गैस कैप्चर
- औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन
- पशुधन अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ

इन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय तंत्र जैसे

Kyoto Protocol के तहत Clean Development Mechanism (CDM) का उपयोग किया गया।

Conclusion:

मीथेन उत्सर्जन में कमी जलवायु परिवर्तन को धीमा करने का एक तेज और प्रभावी उपाय है। इसलिए भविष्य की जलवायु नीतियों में मीथेन नियंत्रण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Short-lived climate pollutant concept • Methane lifetime (≈ 12 years) • High warming potential • Climate policy linkage • Real project examples 	<ul style="list-style-type: none"> • CO₂ और मीथेन का अंतर स्पष्ट न करना • उदाहरणों का अभाव • केवल सैद्धांतिक उत्तर लिखना • जलवायु नीति से संबंध न जोड़ना

PRAYAGRAJ

NEW BATCH
GENERAL STUDIES
IAS/PCS

हिन्दी माध्यम

30 March
8:30 AM

ENGLISH MEDIUM

25 March
8:00 AM

Project अनुशीलन

Integrated Test & Mentorship Program

Starts from 25 March

IAS/UPPCS PRELIMS
90/80 Test

IAS/UPPCS MAINS
76/80 Test

ALIGANJ, LUCKNOW

NEW BATCH
GENERAL STUDIES
UPPCS

30 March | 9:00 AM & 6:00 PM

GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NEW BATCH
GENERAL STUDIES

UPSC (IAS)

25 March
12:00 PM

UPPCS

25 March
8:30 AM

PRAYAGRAJ : 8853467068

ALIGANJ: 7619903300

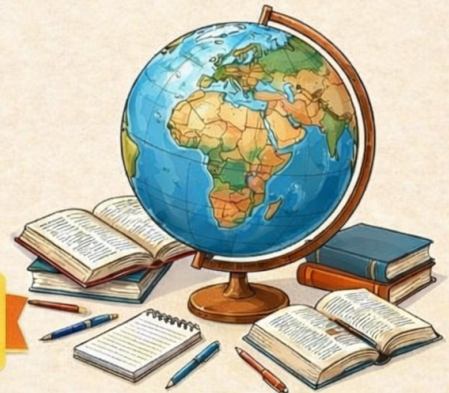
GOMTI NAGAR: 7570009003

NEW BATCH
General Studies
IAS/PCS
(English Medium)

25th MARCH 2026

8:30 am

OPEN TO ALL
FOR 3 DAYS



S.P Marg, Civil Lines, Prayagraj

8853467068